>

Title: Need to ensure electrification of all the villages in Jhanjarpur Parliamentary Constituency, Bihar as per specified norms.

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर) बिहार के मधुबनी जिलान्तर्गत मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र झंझारपुर के क्षेत्राधिकार में जिले के 14 प्रखण्ड आते हैं। इन 14 प्रखण्डों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य अत्यंत ही असंतोषप्रद है। हमारे संसदीय क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य करने की एजेंसी एनएचपीसी है, जिसने ए–टू–जेड नाम की एजेंसी को इस कार्य को कार्यान्वित करने का ठेका दे रखा है। यहाँ विद्युतीकरण का कार्य सभी गाँवों में समान रूप से नहीं हो रहा है तथा इसमें काफी अनियमितताएँ पाई गई हैं। जिन गाँवों में विद्युतीकरण किया भी गया है वहाँ भी इसे पूर्ण रूप से मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है। फलतः ऐसे गाँवों के जो बीपीएल परिवार हैं, वे इस योजना से सम्पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि 10,16 और 25 केवीए की क्षमता वाले ट्रंसफार्मर को अधिष्ठापित किए जाने के फलस्वरूप 15 दिनों अथवा एक माह के अंदर अधिकांश ट्रंसफार्मर या तो जल चुके हैं अथवा कई कारणों से दोषपूर्ण हो चुके हैं, जिनके पुनराधिष्ठापन की कार्रवाई एनएचपीसी के द्वारा बार–बार कहने के बावजूद नहीं की जा रही। यह योजना इसलिए भी विफल हो रही है कि इसका डीपीआर त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण डीपीआर होने के बावजूद यदि सर्वेक्षित गाँवों और टोलों को योजनानुसार ईमानदारी से विद्युतीकरण किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे गाँवों/टोलों सहित बीपीएल के लाभार्थियों को काफी लाभ मिल सकता है। किन्तु ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इसकी समीक्षा और अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) करने की जिला स्तर पर कोई आधिकारिक न तो प्राधिकार है और न इसके लिए सक्षम और दायित्व बॉडी का ही गठन किया गया है। फलतः एनएचपीसी और इसके मातहत की एजेंसी ए–टू–जेड पर किसी का न तो नियंत्रण है और न ही अंकुश। अचरज तो यह है कि एनएचपीसी और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में किसी प्रकार का कोई तालमेल और समन्वयन भी नहीं है। यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके चलते राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण की यह योजना धरातल पर अब तक नहीं उतर पाई है जिसके कार्यान्वयन पर सरकार करोड़ों रुपए निरर्थक व्यय कर रही है।

अतः मैं इस दिशा में शीघ्र समुचित कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।